चलेंगे तो उनका फिजिकल परफारमेंस और फाइनैंशियल परफारमेंस हमेशा गड़बड़ी का रहेगा और गड़बड़ी का रहा है और उसके परिणामस्वरूप पूरे ऊर्जा क्षेत्र को सफर करना पड़ रहा है ।

जहां तक रि-स्ट्रक्चरिंग का सवाल है, हम लोगों ने जनवरी, 1993 में स्टेट पावर मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस की थी और उसमें कुछ फैसले लिए थे । उसमें यह बहुत अहम फैसला लिया था कि प्लांट लोड फास्टर बढ़ाया जाए, ट्रांसमीशन डिस्ट्रिब्यूशन लॉसिस कम किए जाएं । उसमें यह भी फैसला लिया था कि जहां तक कृषि के क्षेत्र में ऊर्जा की दरों का सवाल है, टेरिफ का सवाल है, वह कम से कम 50 पैसा प्रति किलोवाट अगर हो जाए, अब उस पर कुछ राज्यों ने तो अमल किया है, कुछ राज्यों ने अमल नहीं किया है । अध्यक्ष जी, यह कन्करेंट सब्जेक्ट है । उनका अधिकार, उनकी अथारिटी उतनी है जितनी हमारी है । उनके अधिकार क्षेत्र में हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते । अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है, वह कर रहे हैं, उनके फाइनैंसिस अच्छे हों । फाइनैंशियल पैरामिटर्स और ऑपरेशनल पैरामीटर्स जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं और यह लगातार करते रहेंगे । इस सिलसिले में अगर माननीय सदस्य हमारी कुछ मदद कर सकें तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा क्योंकि दिक्कत यह है कि जो दरों का सवाल है, बहुत अहम सवाल है । जो राज्य सरकारें हैं, वह एक नीति निर्धारित करती है अपने लिए कि जहां तक अलग-अलग दायरों का, अलग-अलग एरियाज का, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, एक अलग-अलग रेट हो और उसमें अगर राजनीति आने लगे तो वही होगा जो हो रहा है । यह दरअसल सब मुद्दों का एक मुद्दा है, यह मेरा निवेदन है।

सभापति : सैकिंड सप्लीमेंटरी ।

डा० बापू कालदाते : नहीं । यह पूछ लें ।

श्रीमती कमला सिन्हा : अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी । मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि यह कन्करेंट सब्जेक्ट है और प्रांतों को इसके बारे में देखना होगा । बात तो सही है लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि क्या यह सही है कि पूर्वी प्रांतों में से, जहां से ऊर्जा का जो रा-मेटीरियल है कोयला, वह ज्यादा तो पूर्वी प्रांतों से, ही आता है, जैसे बिहार । बिहार से 40 प्रतिशत कोयले का उत्पादन होता है और ऊर्जा का उत्पादन दूसरे प्रांतों में है । बिहार तो पावर स्टार्व्ड स्टेट है । उसी तरह से उड़ीसा, बंगाल है, पिछले तीन सालों में इनकी ऊर्जा की खपत गिरी है । तो क्या यह सही है कि पिछले 30—40 सालों में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तहत कारखाने लगाए गए थे, उनका नवीनीकरण नहीं हुआ और केन्द्रीय सरकार ने कोई ऊर्जा का कारखाना वहां लगाया ही नहीं और इसीलिए यह एस०ई०बी० भी बीमार पड़ रहा है और साथ-साथ प्रांत भी पीछे हो रहे है, क्या यह बात सत्य है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : अंशतः सत्य है, अंशतः असत्य है ।

श्रीमती कमला सिन्हा : पूर्णतः सत्य है ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : ईस्टर्न सेक्टर में इस्टर्न ग्रिड है । ईस्टर्न ग्रिड में हमने बहुत सारे कारखाने लगाए हैं और ईस्टर्न ग्रिड को और दूसरे ग्रिड के मुकाबले में पर्याप्त पावर दी जा रही है । मगर पहला सवाल जो आपने किया, वह बिल्कुल सत्य है कि जहां कोयला होता है वहां कारखाने लगें, ऐसी कोई नीति अभी नहीं है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि नयी नीति में हम चाहते हैं कि जहां कोयले की खदानें हों वहां ही कारखाने लगें बल्कि ऊर्जा के कारखाने वहीं लगें । यह बहुत जरूरी है । मैं एक चीज और बता दूं कि इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न और है कि सस्ता कोयला मिल जाए तो पावर का जो ट्रांसमिशन है, वह ज्यादा सस्ता पड़ता है । यही मेरा निवेदन है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Now Papers to be laid on the Table of the House—Shri Sukh Ram.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Privatisation of Power Plants in Maharashtra

•183. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for privatisation of any major power plant in Maharashtra;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the stage at which this proposal stands and by when the final decision is likely to be taken ?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

News Coverage for various Political Partie*

♦186. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is definite tilt at present in favour of ruling party in respect of news coverage on Doordarshan and A.I.R, networks;